International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 6, September-October 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

भारत-पाक संबंध: वर्तमान परिप्रेक्ष्य

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Department of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत और पाक के मध्य रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव भी देखे गये, उरी और पठानकोट हमलें के समय दोनों देशों के रिश्तों पूरी तरह तल्ख हो चुके हैं.

इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के राजयनिक सम्बंध भी बिगड़ गये हैं. हालांकि कोरोना महामारी में भारत ने अपने पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सीन नीति के तहत पाकिस्तान को भी निशुल्क वैक्सीन दी गई.

दोनों देशों के मध्य व्यापारिक रिश्ते पूरी तरफ ढप हैं. प्राणरक्षक दवाइयों के अतिरिक्त अन्य किसी तरह के उत्पादों पर आयात पर पाकिस्तान सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगाई गई हैं.

जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A की बर्खास्तगी और दो बड़े आतंकवादी हमलों के बाद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं. आने वाले कुछ वर्षों में रिश्तों में सुधार देखे जा सकते हैं.

दो संगे भाइयों की तरह एक ही देश के विभाजन से जन्में भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से ही कटुतापूर्ण रहे हैं. पाकिस्तान ने कश्मीर प-आर 22 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर, इस दुश्मनी के बीज बो दिए था. भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने अन्यायपूर्ण तरीके से दबा कर रखा हैं.

भारत ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका के रूप में पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ दिया हैं, जबकि पाक कभी चीन कभी अमेरिका से मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र तैयार करने में कोई कसर नही छोड़ी.

दोनों देश चार बड़े युद्धों की विभिशसा को देख चुके हैं, सीमा पार दोनों ओर की जनता अमन चैन से अपने अपने वतन का विकास चाहती हैं, वही पाकिस्तान हर वक्त नये जुगाड़ में लगा रहता हैं, कैसे भारत की टांग अड़ाई जाएं.

How to cite this paper: Dr. Dhiraj Bakolia "Indo-Pak Relations: Current Perspectives" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-6, October 2022, pp.1793-1797, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52172.pdf

IJTSRD52172

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचय

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्ध अपने निम्नतम स्तर पर रहे. ख़ास कर इमरान की भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में पब्लिक रेलियों में बदजुबानी और अपमानसूचक शब्दों के प्रयोग भी देखे गये.[1,2]

२०१८ से २०२२ इन चार वर्षों में भले ही बॉर्डर पर सीज फायर की स्थिति लम्बे समय तक बरकरार रही, मगर रिश्तों में कडवाहट ही रही. दोनों देशों के हेड ऑफ़ स्टेट के मध्य फोन कॉल संवाद भी समाप्त हो गये थे. बाईडन कॉल करता नहीं मोदी फोन उठाते नहीं यह उक्ति इमरान को घेरने के लिए हमेशा विपक्षी दल खान को घेरते थे.

पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद खान ने भारत विरोधी राग को हर जगह अलापा. हालांकि संसद में अविश्वास मत पास होने के बाद जब इमरान अपदस्थ हुए तो उन्होंने एक के बाद एक हर पब्लिक रेली में भारत और भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफे की थी.

अंतिम वायसराय लोर्ड माउंट बेटन की विभाजन योजना के अनुसार सभी रजवाड़ों तथा रियासतों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया, कि वे चाहे तो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के अथवा वे स्वतंत्र रूप से अलग भी रह सकते है. इस तरह हैदराबाद व जूनागढ़ की तरह जम्मू कश्मीर ने भी स्वयं को किसी भी देश में न मिलाकर स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था.

पाकिस्तान द्वारा बार बार प्रलोभन के मौके मिलने के उपरांत भी जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके उकसावे की निति के तौर पर पाकिस्तानी ने अक्टूबर 1948 में हरिसिंह के सम्पूर्ण राज्य पर काबाइली हमला कर दिया.[3,4]

हरिसिंह भारत के पास सैन्य सहायता के लिए आए, उस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय के सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये, तदोपरान्त भारतीय सेना ने मौर्चा संभाला तथा 24 घंटों में युद्ध को पूर्व स्थति में ला दिया. पाकिस्तानी घुसपैठियों जान बचाकर भाग गये, सेना पीछा करती हुई लाहौर तक चली गईं, युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेनाएं वापिस बुला ली गईं.

इसी समय भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु एक बड़ी चूक कर जाते हैं, जिनका खामियाजा आज तक भारत के लोग भुगत रहे हैं. इस विषय के हल के लिए वे संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर विवाद को किसी हल के लिए ले जाते हैं. मगर आज भी कश्मीर विवाद यू का यू पड़ा हैं, जिस पर किसी तरह का समाधान नही निकल पाया हैं.

पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से POK पर कब्जा कर रखा हैं, वही वो कश्मीर घाटी में आए दिन घुसपैठ व आतंकवादी भेजकर इंडो पाक रिलेशन को उसी स्थति में रहने देना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना का राजनीति पर वर्चस्व कायम रहे.

अप्रैल 1965 में पाक की ओर से घुसपैठिये भेजकर कच्छ के रन तथा कश्मीर में घुसपैठ की शरारत की गईं, लाल बहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व में पाक की इस हरकत को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सैन्य सैन्य कार्यवाही शुरू की गईं, जो 1965 के भारत पाक युद्ध में बदल गईं.[5,6]

4 महीने तक दोनों देशों के बिच जंग चलती रही, 22 अक्टूबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ की दखल से यह युद्ध समाप्त हुआ, मगर इससे पूर्व ही पाकिस्तान के सैनिक हथियार डालकर भाग चुके थे.

तक़रीबन 7-8 माह बाद सोवियत संघ रूस उस समय भारत का परम मित्र था, उसके कहने पर भारत पाक समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में सम्पन्न हुआ, लेकिन इस दौरान ताशकंद गये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गईं थी.

विचार-विमर्श

इस समझौते के उपरान्त कुछ साल शान्ति पूर्ण तरीके से गुजर ही रहे थे, कि पूर्वी पाकिस्तान में याहया खान के अत्याचारों के कारण गृहयुद्ध शुरू हो गया. वहां के बंगाली भारत में आकर शरण लेने लगे.

नई दिल्ली में आने वाले बंगलादेशी शरणार्थीयों की संख्या 1 करोड़ तक पहुच गईं, भारत ने उनके खाने पीने तथा अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की तथा उन्हें मेहमान स्वरूप रखा.

जो पाकिस्तान को नागवार गुजरा, उसने 2 दिसम्बर 1971 को वायुसेना से भारतीय एयरबेस पर हमला शुरू कर दिया. भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब दिया, इस जवाबी कार्यवाही में कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए, तथा एक नये राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ.[7,8]

1971 के इंडिया पाक वॉर के बाद 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया गया. इस समझौते में भारत ने पाकिस्तान को के साथ युद्ध के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए सरेंडर कर चुके 90,000 सैनिकों सहित विजित क्षेत्र को पाकिस्तान को लौटा दिया. यह वजह हैं कि आज भी इसे भारत की सबसे बड़ी कुटनीतिक हार माना जाता हैं.

वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध तथा 1972 के शिमला समझौते के बाद दोनों देशों के बिच सामाजिक, धार्मिक, राजनितिक व आर्थिक सम्बन्धों में सुधार हो रहा था, कि 1979 को सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, भारत सोवियत

संघ के साथ था,जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का समर्थक था. इसके चलते दोनों देशों के संबंध एक बार भी कटुताभरे रहे.

1985 में भारत की ओर से एक बार फिर मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की पहल की, मगर भारत का यह प्रयास नाकाम रहा. कुछ वर्ष बाद 1998 में भारत ने पोकरण में अमेरिका की आँखों में धूल झोकते हुए अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था.

जिससे एक बार फिर दोनों में कटुता पूर्ण संबंध स्थापित हो गये. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाक के सबंधों में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किये,जिनमें 1999 में ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा का शुभारम्भ किया.

पाकिस्तान हमेशा अपनी पालिसी के अनुसार कार्य करता रहा, भारत के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में फिर से घुसपैठ शुरू कर दी. जिसका नतीजा भारत पाकिस्तान के मध्य एक और युद्ध जिसे कारगिल युद्ध कहा जाता हैं, के रूप में सामने आया. इस युद्ध में भी पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी. मगर इससे संबंध फिर से खराब होने लगे.

दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार के लिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशरफ के मध्य आगरा सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन में भी पाकिस्तान के प्रतिनिधि की कश्मीर हठ के कारण बातचीत आगे नही बढ़ पाई, तथा यह समझौता भी बेनतीजा ही रहा. एक बार फिर दोनों देशों के सम्बन्धों में दरार जब आई तब 2001 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय संसद भवन पर आतंकवादी हमला किया. वर्ष 2003 तक दोनों देशों के रिश्तों में कटुता रही.[9,10]

एक बार फिर 20 जनवरी 2006 को लाहौर और अमृतसर के मध्य बस सेवा शुरू होने से दोनों देशों की जनता की शान्ति की नई उम्मीद जगी. मगर 26 नवम्बर 2008 को पाकिस्तान द्वारा मुंबई की ताज होटल पर किये जाने से पूरे विश्व को यह पता चल गया, कि पाकिस्तान के साथ मित्रता सांप को दूध पिलाने जैसा हैं

सन 2000 से लेकर 2018 तक भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हर मौके पर उन्हें और विश्व को सबूत पेश किये, जाने के उपरांत भी. पाकिस्तान द्वारा इन्हें रोकने की बजाय आतंकवाद को पोषण देकर हर तरह की सुविधा देने में जुटा हैं. हर मंच पर भारत की बात न सुनकर कश्मीर की राग अलापने से भारत पाक सम्बन्धों में कभी भी सुधार नही आ सकता.

वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्वकप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत खेलने आई थी. इस दौरान भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सेमीफाइनल मैच के दौरान युसूफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह दोनों एक साथ बैठकर मैच का आनन्द ले रहे थे. क्रिकेट तथा परस्पर सांस्कृतिक व फिल्म जगत के कारण भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरे हैं.

2016-17 में उरी, पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमलों तथा 2018 में आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के चलते आज फिर दोनों देशों के बिच तनातनी का माहौल बना हुआ हैं. कुलदीप जाधव मामला भी दोनों के राजनितिक/कुटनीतिक तथा राजनितिक संबंधो में भी खटास का कारण रहा हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की हर संभव कोशिश की गईं, चाहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को न्यौता हो या नवाज शरीफ के कार्यक्रम में मोदी का अचानक जाना, मोदी की ओर से उठाए गये, सकारात्मक कदमों में से हैं.

दूसरी तरफ भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके यह जता दिया, हम दोस्त को दोस्ती निभाते हैं, दुश्मन के साथ दुश्मनी निभानी भी हमे आती हैं.

परिणाम

जनवरी महीने में पाकिस्तान ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की. ये सुरक्षा नीति, सुरक्षा के क्षेत्रीय वातावरण को लेकर पाकिस्तानी तंत्र की सोच और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़तरों का ख़ाका पेश करती है. इस दस्तावेज़ में भारत का ज़िक्र प्रमुखता से किया गया है- ये इस बात को दोहराता है कि पाकिस्तान को अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ख़तरा भारत से ही महसूस होता है. इस दस्तावेज़ में ये भी कहा गया है कि भू-आर्थिक स्थितियां ही पाकिस्तान की भू-सामरिक झुकाव को तय करेंगी. हालांकि, अपनी लगातार घटती आर्थिक हैसियत, मध्य या दक्षिणी पूर्वी एशियाई बाज़ारों के साथ कोई संपर्क न होने और चीन से लिए गए क़र्ज़ के बढ़ते बोझ के चलते, पाकिस्तान की भू आर्थिक महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने से पहले ही ढेर होती दिखती हैं. अब सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, पाकिस्तान की इस सुरक्षा रणनीति से कैसे निपटे? आज़ादी के बाद से ही, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की साज़िशों और सीमा पर उसकी हरकतों ने भारत के सुरक्षा तंत्र को उलझाकर रखा हुआ है. भारत ने पाकिस्तान की इस चुनौती से निर्णायक तरीक़े से निपटने के लिए, पारंपरिक सैन्य शक्ति में अपनी ज़्यादा ताक़त का इस्तेमाल किया है. हमने इसके नतीजे पहले 1965 और फिर 1971 के युद्धों में पाकिस्तान की हार के रूप में देखे हैं. यहां ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान से सैन्य तरीक़े से निपटने की भारत की इस कोशिश का असर, हमने 1950 और 60 के दशक में चीन के ख़तरे से संतुलन न बना पाने के रूप में देखा है [1] . इसक बावजूद, भारत के नीति निर्माताओं के ज़हन में हमेशा पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौती अहम रही है. दोनों देशों द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने के चलते, उनके बीच के सुरक्षा समीकरण और भी जटिल हो गए हैं.[11]

सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर

जब पाकिस्तान, पारंपरिक सैन्य ताक़त में भारत से पार नहीं पा सका, तो उसने भारत को 'हज़ारों जख़्मों से लहूलुहान' करने की ग़ैर-पारंपरिक युद्ध नीति पर अमल करना शुरू किया. जम्मू-कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान की सेना द्वारा अलगाववादी विद्रोह को सक्रियता से बढ़ावा दिया गया. इसके अलावा, बाद में पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को भी बढ़ावा दिया. क्रिस्टीन सी. फेयर ने इसे 'परमाणु सुरक्षा कवच की आड़ में जिहाद' का नाम दिया है. अपनी इस नीति के चलते पाकिस्तान ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत का सुरक्षा तंत्र आतंकवाद की समस्या से निपटने में ही उलझा रहे.

भारत की सबसे बड़ी चिंता ये रही है कि अगर वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ख़िलाफ़ पलटवार करता है, तो कहीं संघर्ष बढ़ न जाए और परमाणु युद्ध की नौबत न आ जाए.

जब भी सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से निपटने की बाद आई है, तो भारत का सुरक्षा तंत्र, पारंपरिक रूप से कोई जोखिम लेने से बचता रहा है. भारत की सबसे बड़ी चिंता ये रही है कि अगर वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ख़िलाफ़ पलटवार करता है, तो कहीं संघर्ष बढ़ न जाए और परमाणु युद्ध की नौबत न आ जाए. 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद, भारत के नीति निर्माताओं ने सैन्य हमले के विकल्प पर गंभीरता से ग़ौर ज़रूर किया. लेकिन, जैसा कि पूर्व विदेश सचिव और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिवशंकर मेनन ने बताया है कि तत्कालीन सरकार ने आख़िरकार ऐसा क़दम न उठाने का फ़ैसला किया था.

लेकिन, जैसे जैसे हाल के दिनों में आतंकवादी घटनाओं की रफ़्तार में तेज़ी आई, तो भारत ने राजनीतिक इच्छाशक्ति के समर्थन से अपने रक्षात्मक रवैए को अलविदा कह दिया. किसी आतंकवादी हमले के बाद भारत के सुरक्षा तंत्र ने सैन्य अभियानों जैसे कि 'सर्जिकल स्ट्राइक' (सितंबर 2016) और बालाकोट हवाई हमले (फ़रवरी 2019) के ज़रिए पलटवार किया और ये दिखा दिया कि वो पाकिस्तान की परमाणु युद्ध की धमकी की हवा निकालना भी जानता है. भारत की सैन्य कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान की तरफ़ से ठोस जवाब न मिलने से ये ज़ाहिर हो गया कि भारत ने बहुत सोच-समझकर जोखिम लिया था. अब इन कार्रवाइयों ने भविष्य में सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों के जवाब का तरीक़ा तय कर दिया है.

हो सकता है कि आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई ने भविष्य में पाकिस्तान की तरफ़ से ऐसी हरकतों पर लगाम लगा दी है. वैसे अब किसी भी स्थिति में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को भविष्य में कोई साज़िश रचने से पहले इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि भारत इसके बदले में सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है. लेकिन, पाकिस्तान को अपनी आतंकवादी गतिविधियों को नया रंग-रूप देने और नए नुस्खे आज़माने का हुनर हासिल है. ये बात हमें कुछ मिसालों से साफ़ नज़र आती है. पहले जहां पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत के अहम शहरों में बहुत सारे लोगों को शिकार बनाने वाले आतंकवादी हमले (2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके, 2008 का मुंबई आतंकी हमला) करते थे. उसके बाद, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सीमा के क़रीब भारत के सुरक्षा बलों और उनके ठिकानों (2015 में गुरदासपुर, 2016 में पठानकोट और उरी, 2019 में पुलवामा) को निशाना बनाने लगे.[10,11]

अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक और संवैधानिक बदलाव किए, तो उसके बाद पाकिस्तान की इस रणनीति में और भी बदलाव देखा जा रहा है. उसके बाद से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी, स्थानीय समर्थन के नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर कश्मीर घाटी के अंदर बहुत छोटे छोटे आतंकवादी हमले कर रहे हैं. इन हमलों में सुरक्षा बलों, आम लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. ये घटनाएं इतने छोटे पैमाने पर अंजाम दी जा रही हैं कि सुरक्षा बलों को स्थानीय स्तर पर ही कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है और पाकिस्तान, ऐसे हमलों की कोई क़ीमत चुकाने से बच जाता है.

भारत के सुरक्षा तंत्र को कश्मीर घाटी के इन नए हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी, वरना ऐसे हमलों से अगस्त 2019 में किए गए बदलावों से हुए ज़मीनी फ़ायदे, भारत के हाथ से निकल जाएंगे.

भारत के सुरक्षा तंत्र को कश्मीर घाटी के इन नए हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी, वरना ऐसे हमलों से अगस्त 2019 में किए गए बदलावों से हुए ज़मीनी फ़ायदे, भारत के हाथ से निकल जाएंगे.

पाकिस्तान हमेशा दबाव में रहे और उसे भारत की ओर से कड़ी कार्रवाई का डर बना रहे, इसके लिए भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान, आतंकवाद को धन मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी से न बच निकले. ख़ास तौर से भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) जैसे मंचों पर पाकिस्तान द्वारा हवाला के अवैध माध्यम से आतंकवादियों की वित्तीय मदद करने की करतूतों को उजागर करते रहना होगा. क्योंकि, पाकिस्तान इसी के ज़रिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के विशाल नेटवर्क को पालता पोसता आया है. कश्मीर घाटी में आतंक के इसी हवाला नेटवर्क के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा पिछले कुछ साल से की जा रही कार्रवाई बिल्कुल सही दिशा में उटा क़दम है. इसके अलावा, जैसा कि राजेश राजगोपालन ने कहा है कि भारत को, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी लगातार विरोध करते रहना होगा, और दुनिया को ये बताते रहना होगा कि पाकिस्तान ने गिल्गित बाल्टिस्तान पर अवैध क़ब्ज़ा कर रखा है, जबकि वो भारत का हिस्सा है. ये मुद्दा उठाने से भारत, चीन पर भी पलटवार कर सकेगा.

हालांकि, पाकिस्तान के कायराना रवैये के ख़िलाफ़ सख़्त रवैया अपनाते हुए भी भारत के पास एक अवसर है कि वो कश्मीर में सुरक्षा बलों को राहत की सांस लेने का मौक़ा दे. अगस्त 2019 में उठाए गए क़दमों के बाद जो सियासी माहौल बना है, उसका फ़ायदा उठाकर भारत ऐसा कर सकता है और लंबी अवधि के लिए अपनी स्थिति मज़बूत कर सकता है.[8,9]

निष्कर्ष

साइबर दुनिया

सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर के अलावा पाकिस्तान ने साइबर क्षेत्र के मोर्चे पर भारत के ख़िलाफ़ अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं. हाल के वर्षों में भारत के कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमलों की बढ़ती तादाद और सोशल मीडिया मंचों पर भारत के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार से ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है. पाकिस्तान स्थित हैकर अब सिर्फ़ भारत की वेबसाइट हैक करके उस पर ऊल-जलूल बातें लिखने तक ही सीमित नहीं हैं. बल्कि, अब वो 'रिवर्सरैट 2.0' जैसे साइबर हमले भी कर रहे हैं, जिनके निशाने पर सरकारी अधिकारी और कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, और जिनकी मदद से गोपनीय डेटा चुराकर भारत की क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की सेवाओं में ख़लल डाला जा सके.

भारत ने डिफेंस साइबर एजेंसी जैसी संस्थाओं का गठन करके अपनी साइबर सुरक्षा को पहले से मज़बूत बनाया है, जिससे ऐसे हमलों का जवाब दिया जा सके. इसके साथ साथ भारत को पाकिस्तान की साइबर सुरक्षा नीति की तर्ज पर ख़ुद भी आक्रामक रणनीति बनानी होगी. पाकिस्तान ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति में साफ़ तौर पर ये कहा है कि 'पाकिस्तान के क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले को देश की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा'. पाकिस्तान ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति में ये भी कहा है कि अपने अहम साइबर ढांचे पर होने वाले हमले के 'जवाब में पाकिस्तान भी आवश्यक क़दम उठाएगा'. अपनी जल्द ही सामने आने वाली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति में भारत को भी अपनी आक्रामक साइबर क्षमता को केंद्र में रखना चाहिए.

पाकिस्तान स्थित हैकर अब सिर्फ़ भारत की वेबसाइट हैक करके उस पर ऊल-जलूल बातें लिखने तक ही सीमित नहीं हैं. बल्कि, अब वो 'रिवर्सरैट 2.0' जैसे साइबर हमले भी कर रहे हैं, जिनके निशाने पर सरकारी अधिकारी और कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, और जिनकी मदद से गोपनीय डेटा चुराकर भारत की क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की सेवाओं में ख़लल डाला जा सके.[10]

इस वक़्त दुनिया में बड़ी ताक़तों के बीच जैसे तल्ख़ रिश्ते हैं, वैसे में हमें विश्व स्तर पर किसी साइबर समझौते या सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. साइबर दुनिया की इस अराजकता के बीच तमाम देशों के पास बस एक ही विकल्प है कि वो आक्रामक रुख़ अपनाएं. इसीलिए, भारत को न सिर्फ़ अपने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को और लचीला बनाना चाहिए, बल्कि ख़ुद को साइबर दुनिया में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से निपटने के लिए भी तैयार करना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई बार गंभीर प्रयास करने के बावजूद भारत, पाकिस्तान के साथ अपने ख़राब रिश्तों को दुरुस्त कर पाने में नाकाम रहा है. इसके बजाय, भारत के तमाम प्रयासों की नाकामी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और रिश्ते सुधारने को लेकर भारत के सुरक्षा तंत्र के नाउम्मीदी भरे नज़रिए को ही मज़बूती दी है.

इसके अलावा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय होड़ और सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक प्रभाव के मामले में दोनों देशों के बीच बढ़ते अंतर ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव की उम्मीदों को भी काफ़ी सीमित कर दिया है. हो सकता है कि पाकिस्तान, जियोइकॉनमिक्स के पर्दे की आड़ में अपनी भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छुपाना चाहे. लेकिन वो इस क्षेत्र को अस्थिर बनाने में अपनी नकारात्मक भूमिका पर पर्दा नहीं डाल सकता है. जब तक पाकिस्तान का शासक वर्ग और सैन्य तंत्र कश्मीर, आतंकवादी संगठनों को मदद और भारत विरोधी दुष्प्रचार की अपनी नीति में बुनियादी तौर पर बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक भारत द्वारा अपने रुख़ में कोई बदलाव करने की कोई संभावना नहीं दिखती है.[11]

संदर्भ

[1] "सिंधु जल समझौते के उल्लंघन को 'युद्ध के लिए उकसाने' के तौर पर लिया जाएगा: पाकिस्तान". मूल से 28 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[2] "सिंधु जल संधि के मसले पर पाकिस्तान ने विश्व बैंक का रुख किया". मूल से 28 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[3] "पाकिस्तान पड़ा अलग-थलग - भारत के बाद तीन और देशों ने किया सार्क सम्मेलन में शिरकत से इंकार". एनडीटीवी खबर. मूल से 29 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[4] "पाकिस्तान को दिए 'सबसे तरजीही मुल्क' के दर्जे पर पुनर्विचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी". मूल से 28 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[5] "कल रात हमने LoC पर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल हमला किया: विदेश, रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में DGMO". एनडीटीवी खबर. मूल से 2 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[6] Khan, MH (5 March 2006). "Back on track". Dawn News archives. मूल से 28 जून 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 April 2013.

[7] इस तक ऊपर जायें:अ आ PBS Release (July 26, 2005). "Border Jumpers The World's Most Complex Borders: Pakistan/India". PBS. मूल से 23 मार्च 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 April 2013.

[8] PHILIP WALKER (June 24, 2011). "The World's Most Dangerous Borders". The Foreign Policy. मूल से 24 मार्च 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 April 2013.

[9] "Dailymail". मूल से 20 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 October 2014.

[10] "India-Pakistan Borderlands at Night". India-Pakistan Border at Night. NASA. 23 September 2015. मूल से 6 अक्तूबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 October 2015.

[11] "Annotated image from NASA". मूल से 21 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 सितंबर 2017.